

एस. पी. गोयल और जी. सी. मिताल, न्यायाधीशों के समक्ष।

मदन लाल —याचिकाकर्ता,

बनाम

अमर फूल और अन्य —प्रतिद्वंद्वी

नागरिक पुनरीक्षा संख्या 2877/1983

18 सितंबर, 1985

नागरिक प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम)—क्रम अनुच्छेद 21, नियम 90, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है—नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (1976 का अधिनियम)—धारा 72 और 97—एक डिक्री के क्रियान्वयन में संपत्ति की बिक्री—प्रक्षेपण के बाद जो आप्त होते हैं अभिकर्ता को नकार दिया जा सकता है क्या बोली जा सकती है—नागरिक संहिता के अनुसार जोड़ा गया नियम—क्या 1976 के संशोधन के प्रभाव से निरस्त हो गया है।

निर्णय, कि नागरिक प्रक्रिया नियम 21 की धारा 90 की संशोधन के पूर्व और नागरिक संहिता की संशोधन की तारीख में संपत्ति की बिक्री के बाद, आपत्ति प्राप्त व्यक्ति को अपील करने का अधिकार था, जो घोषणा के प्रकाशन के संबंध में आपत्ति शामिल कर सकता था, प्रायश आपत्ति दिखाने के साथ। इसके अतिरिक्त, 1932 में पंजाब हाई कोर्ट ने एक प्रावधान जोड़ा था जो कि संशोधित अधिनियम के बाद भी जारी रहा ताकि बिक्री के बाद की आपत्तियों के व्यापार को संकुचित करें और नागरिक संहिता के धारा 21 के अनुसार आपत्तियों की सीमा को कम करने के लिए ताकि नागरिक प्रक्रिया में देरी न हो। पंजाब संशोधन के निर्देशों के तहत, निवाला संपत्ति के खिलाफ आपत्तियां उठाई नहीं जा सकती थी जो आवेदक ने बिक्री संचालित करने से पहले उठानी चाहिए थीं। इसलिए, पंजाब के निर्देशों के आधार पर, बिक्री की प्रकाशन के खिलाफ आपत्तियां बिक्री के बाद होनी चाहिए थीं। 1976 के संशोधन के बाद नियम 90 अलग तरीके से शब्दित है। इस नियम में उपनियम 3 का अध्याय नियमानुयायी के लिए समय बचाने के दृष्टिकोण से बनाया गया है लेकिन यह उपनियम पंजाब हाई कोर्ट द्वारा जोड़ी गई प्रोविज़ो से सामर्थ्य बहुत ही अलग है। उपनियम 3 प्रदान करता है कि बिक्री को निरस्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा जिसका आधार बिक्री के प्रकाशन के तिथि के बाद आवेदक ने रखा हो। इसका अर्थ है कि आवेदक द्वारा बिक्री के प्रकाशन के बाद और बिक्री की तिथि तक जो आपत्तियां उपलब्ध होती हैं, वे नागरिक संहिता की धारा 21 के अनुसार बिक्री के बाद भी उठाई जा सकती हैं। उपनियम (3) और पंजाब हाई कोर्ट द्वारा जोड़ी गई प्रोविज़ो के बीच अंतर है। संशोधित अधिनियम की धारा 97 निरस्ति और बचत के संबंध में है। कानून के अधिनियम की धारा 97 के उपशीर्षक 2 की श्रेणी (ग) अधिनियमित नियम की लागूता को संविदित प्रक्रियाओं के लिए बचाती है। जहां प्रक्रियाएं चल रही हैं, वहां पुराने प्रावधान जारी रहेंगे,

लेकिन जहां प्रक्रिया चल रही नहीं है, संशोधित नियम 90 लागू होगा और राज्य विधानमंडल या उच्च न्यायालय द्वारा किया गया संशोधन निरस्त हो जाएगा क्योंकि यह केंद्रीय संशोधित प्रावधान के विपरीत है। इसलिए, पंजाब संशोधन द्वारा जोड़ी गई प्रोविज़ो 1976 के संशोधन के बाद निरस्त हो जाएगी।

(पेरा 4 और 5)

नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत अनुरोधपत्र या मांगपत्रिका, हिसार के अतिरिक्त प्रशासनिक जज श्री ईश्वर चंद जैन के न्यायाधीश की आदेश की संशोधन के लिए। जो कि 30 जुलाई, 1983 को हुई थी, उसके खिलाफ की गई है। जो श्री वी. पी. चौधरी, एच.सी.एस. एक जज, प्रथम श्रेणी, हिसार की तारीख 7 मार्च, 1983 को आपील को स्वीकार करने और उस आदेश को रद्द करने के लिए हुई थी, साथ ही नीलामी को भी और अनुयायी न्यायालय को संविधान के अनुसार प्रक्रिया करने के लिए निर्देशित किया गया था, और पक्षियों को उनके वकीलों के माध्यम से 10 अगस्त, 1983 को कोर्ट में प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था।

प्रार्थी के वकील अरुण जैन।

प्रतिवादी के वकील ओ. पी. शर्मा।

निर्णय

जी. सी. मिताल, ज. —

(1) प्रेम प्रकाश ने अमर फूल के खिलाफ 5,000 रुपये की वसूली के लिए एक फैसला प्राप्त किया। उसके प्रक्रियान्वयन के अनुरूप, 15 कनाल 3 मारला भूमि को 13 नवंबर, 1982 को न्यायिक नीलामी में 6,800 रुपये में मदन लाइ के पक्ष में बेच दिया गया। न्यायाधीश-ऋण देने वाले ने नागरिक संघ की कानूनी प्रक्रिया के धारा 21, नियम 90 के तहत आपत्तियां दर्ज की जो कि कारगर से किया गया था। न्यायालय ने निर्वाचन योजना के संबंध में आपत्ति को न्यायाधीश सभा के निर्देशों द्वारा जोड़े गए नियम 90 के प्रोविज़ो के:

“प्रकाशन के बाद आयोजित किया जाना चाहिए था और बिक्री के बाद उस धारा में आपत्तियां उठाई नहीं जा सकती थी।“

न्यायालय के अन्य आपत्तियां बिक्री के कार्यवाही के संबंध में आवश्यक नहीं थीं। ऋणदेयक की अपील पर, शिक्षित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आपत्ति याचिका को मान्यता देने के बाद नीलामी को रद्द कर दिया और मामले को पुनरारंभित करने के लिए निर्वाचन को संविधान के अनुसार प्रक्रिया करने के लिए कोर्ट को वापस भेज दिया। इसका नतीजा यह निकला कि बिक्री की प्राचलित के दौरान 303/2165 भाग बिक्री के लिए आदेश दिया गया था जबकि नीलामी के समय 303/2365 भाग बेचा

गया था और साथ ही नीलामी की घोषणा के अनुसार नीलामी को गांव खेरी में होनी थी, जबकि बिक्री गांव पाबरा में की गई थी। निर्माणाधीन अपीलेंट कोर्ट ने इस तरह की कोई महत्वपूर्णता नहीं देखी जो दायरे खेरी में की गई थी, जबकि बिक्री गांव पाबरा में हुई थी। अदालत ने देखा कि इन आपत्तियों में कोई महत्वपूर्णता नहीं है।

(2) नीलामी-खरीदार ने इस संशोधन में इस मामले में न्यायालय के पास आया है।

(3) शुरूआत में मामला एस। पी. गोयल, जे के सामने आया था और जिसमें एक बिंदु यह था कि नागरिक संघ को विपणन कानून के अनुसार आपत्ति नहीं थी। नीलामी को दोबारा की जानी चाहिए थी क्योंकि उपरोक्त प्रोविज़ो द्वारा उद्धृत प्रक्रिया के साथ आपत्ति उठाने की जरूरत थी। उनकी बात का समर्थन माइ सिंह बनाम मोघा सेंट्रल बैंक लिमिटेड (1) के इस कोर्ट के एकल बेंच के फैसले पर रखी गई थी। उस फैसले के सही होने के बारे में कुछ संदेह था और विशेष रूप से संशोधित विधि के अनुसार यह विचार किया गया। इसलिए, इस मामले को एक बड़ी बेंच द्वारा सुनवाई के लिए भेजा गया था और ऐसे ही हमारे समक्ष मामला प्रस्तुत हो गया। धारा 90, जैसा कि वह मूल रूप से था, अलग था। उसको एक और प्रोविज़ो ने जोड़ा था, जो 7 अप्रैल, 1932 को पंजाब संशोधन द्वारा किया गया था, जो प्रारंभिक रूप से 1976 के संशोधन के बाद भी जारी रहा, जो भारत के विभाजन के बाद भी और 1966 के पुनर्गठन के बाद भी जारी रहा। अब निर्माणाधीन नियम 90, 1976 के संशोधन के बाद इस प्रकार है: —

"(1) जब कोई अचल संपत्ति किसी अदालती आदेश के निष्पादन के लिए बेची जाती है, तो उस आदेश को धरने वाला, या खरीदार, या किसी भी अन्य व्यक्ति, जो संपत्ति की भागीदारी में समान वितरण का हकदार है, या जिनका हित बिक्री से प्रभावित होता है, वह आदेश में या इसके आयोजन में मूल अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए न्यायालय के पास आवेदन कर सकता है।

(2) कोई भी बिक्री, असमान्यता या धोखाधड़ी के आधार पर रद्द नहीं की जाएगी जब तक, साबित तथ्यों के आधार पर, न्यायालय को यह संतोष हो कि आवेदक ने उस असमान्यता या धोखाधड़ी के कारण काफी चोट पाई है।

(3) इस नियम के तहत बिक्री को रद्द करने के लिए किसी भी आवेदन को संविधान नहीं किया जाएगा, जो आवेदक ने बिक्री के प्रकाशन के दिनांक से पहले या उसी दिनांक को जिस दिन नीलामी की घोषणा की गई थी, उठाने हो सकते थे।"

(4) 1976 में नियम 21 के नियम 90 की संशोधन से पहले, न्यायालय के आदेश में संपत्ति की बिक्री के बाद, आपत्ति जाने वाले व्यक्ति को आपत्तियां दर्ज करने का हक था, जो की घोषणा के प्रकाशन के संबंध में भी आपत्तियां शामिल कर सकती थीं, पर उन्होंने भारी चोट साबित की जानी चाहिए थी। जैसा की आर एन मित्रल जे ने माई सिंह के मामले में सही तरीके से देखा था, 7 अप्रैल, 1932 को पंजाब संशोधन द्वारा एक और प्रोविज़ो जोड़ा गया था, जो की 1976 के संशोधन के बाद भी जारी रहा, जो

उपरोक्त है, ताकि बिक्री के बाद दरखास्त की जाने वाली आपत्तियों की दरकार को घटा दिया जा सके, और इस प्रकार की प्रक्रिया में देरी से बचाई जा सके। पंजाब संशोधन के आधार पर, बिक्री के विरुद्ध आपत्ति बिक्री के पहले उठाई जानी चाहिए थी।

(5) 1976 के केन्द्रीय संशोधन अधिनियम संख्या 104 के तहत, नियम 90 अलग ढंग से शब्दित किया गया है। जो उपरोक्त नियम में दिया गया है, उसमें उपनियम (3) में समय बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन उपनियम (3) पंजाब संशोधन द्वारा जो प्रोविज़ो जोड़ा गया था, से सामग्री में अंतर है। उपनियम (3) का मतलब है कि प्रोठेमेशन ऑफ सेल की घोषणा के उठाने के बाद और बिक्री की तिथि तक जो कोई भी आपत्ति आवेदक के लिए उपलब्ध हुई, वह सभी आपत्तियां, न्यायालय के आदेश अनुसार दर्ज की जा सकती हैं। इसलिए पंजाब संशोधन और उपनियम (3) के बीच अंतर है, इसे देखना होगा कि दोनों में से कौन अधिकारी है। नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 97 का अंश (2) और (1) तक है:—

“97) 1 (अधिनियम की प्रारंभिकता से पहले किसी भी राज्य विधानसभा या उच्च न्यायालय द्वारा किया गया कोई संशोधन या प्रावधान, केवल तब तक ही रहेगा, जब तक वह संशोधन या प्रावधान इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के प्रावधानों के साथ सम्मिलित हो।”

अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (2) की क्लॉज (ग) में संशोधित नियम 90 को किसी भी संपत्ति की बिक्री को रद्द करने के लिए चल रही प्रक्रिया में लागू बचाया जाता है। जहां-जहां प्रक्रिया चल रही है, पुराने प्रावधान लागू रहेगा, लेकिन जहां प्रक्रिया चल रही नहीं है, नियम 97 की उपधारा (1) के अनुसार संशोधित नियम 90 लागू होगा और राज्य विधानसभा या उच्च न्यायालय द्वारा की गई संशोधन हो जाएगा क्योंकि यह केंद्रीय संशोधित प्रावधान के विपरीत है। इसलिए, पंजाब संशोधन द्वारा जो प्रोवाइज़ो जोड़ा गया था, वह संशोधन अधिनियम के अनुसार दिनांक 1 फरवरी 1977 को लागू होने के बाद रद्द हो जाएगा।

(6) हम जिस मामले को देख रहे हैं, वहाँ बिक्री 13 नवंबर 1982 को हुई थी, यानी संशोधित नियम 90 का प्रभाव प्रारंभ होने के बाद और इसलिए नीलकंठ, नीलकंठ को आशयित करने वाले वकील सही नहीं थे कि वह पंजाब संशोधन पर निर्भर हो रहे थे। नियम 90 की उपधारा (3) को ध्यान में रखते हुए, फैसला किया गया कि जजमेंट-डेब्टर को बिक्री के घोषणा होने के बाद जो कुछ भी आपत्तियां थीं, वह सभी आपत्तियां उठाई जा सकती थीं। बिक्री की घोषणा अधिनियम 21 की धारा 66 के अंतर्गत की जाती है।

(7) अब यह देखना होगा कि क्या वाक्यांश, जिन पर न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय ने बिक्री को रद्द कर दिया था, वे घोषणा होने से पहले उठाए जा सकते थे या उसके

बाद उत्पन्न हुए मुद्दों से संबंधित हैं। दो मुद्दे हैं, जिनमें से एक है कि जबकि जजमेंट डेक्टर का हिस्सा 303/2165 की सीमा में बिक्री के लिए आदेश था लेकिन नीलकंठ, जो टाइम ऑफ ऑक्शन पर 303/2365 हिस्सा ही बेचा गया था। यह आपत्ति केवल बिक्री के बाद ही उठाई जा सकती थी और इसे घोषणा होने से पहले उठाया नहीं जा सकता था। दूसरी आपत्ति थी कि बिक्री को जहां होना चाहिए था, वहां वह दूसरे गांव में हुई थी। यह भी एक मुद्दा था जो केवल घोषणा होने के बाद उठाया जा सकता था और उससे पहले नहीं। इसलिए, नीलकंठ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जो न्यायिक अपील ने अनुमति दी गई थी, उन्हें जजमेंट डेक्टर द्वारा उठाए जाने का कोई मूल्य नहीं है।

(8) 1976 के संशोधन अधिनियम के बाद जो कानून की बात की गई है, उसके पूर्व न्याय के निर्णय पूरी तरह निरर्थक होंगे। मैं सिंह की यह निर्णय, आर एन मित्तल, जेड की निर्णय और उसमें संदर्भित अन्य मामले संशोधन अधिनियम संख्या 104 1976 के पहले हुए प्रक्रियाओं से संबंधित हैं और इसलिए उनकी अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, धारा 21, नियम 90 के पंजाब संशोधन द्वारा जो प्रोवाइजो जोड़ा गया था, वह दिनांक 1 फरवरी 1977 से प्रभाव से रद्द हो गया है। नियम 90 जैसा कि अब 1 फरवरी 1977 से प्रभाव से है, वैसा ही लागू होगा।

(9) ऊपर दर्ज कारणों के आधार पर, हमें इस संशोधन में कोई मूल्य नहीं लगता है और इसे खारिज किया गया है, जिससे पक्षों को अपना खर्च उठाना पड़ेगा। कानून के अनुसार कार्यान्वयन न्यायालय अब कानून के अनुसार पुनः संलग्न संपत्ति को बेचेगा।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा

(1) 1982 P.L.R. 494 = 1982 R.L.R. 196.